डिजीगंगा

गंगा पवित्रता और निरंतरता का प्रतीक है, ठीक वैसे ही जैसे **एन.आई.सी. उत्तर प्रदेश** की भूमिका ई-गवर्नेंस को सक्षम बनाने में है, जो हर नागरिक के जीवन को प्रभावित करती है।

समाचार पत्रिका

सितंबर 2025

महानिदेशक राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र, श्री अभिषेक सिंह, आईएएस का दौरा

माननीय महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, श्री अभिषेक सिंह, आईएएस, अतिरिक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा सीईओ, इंडिया एआई मिशन ने 18 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश राज्य केंद्र का दौरा किया।

सत्र का शुभारंभ श्री आशेष अग्रवाल, राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी उत्तर प्रदेश द्वारा महानिदेशक का स्वागत पुष्पगुच्छ भेंट कर किया गया।

अपने संबोधन में महानिदेशक ने राज्य/जिला स्तर के सभी अधिकारियों को साइबर सुरक्षा, एआई, माइक्रोसर्विसेज और ब्लॉकचेन जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में सक्रिय रूप से प्रशिक्षण प्राप्त करने की सलाह दी, ताकि नवीनतम प्रगतियों से अद्यतन रहा जा सके।

उन्होंने आगे यह भी निर्देश दिया कि अधिकारी देश के अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी केन्द्रों का भ्रमण करें तथा आईसीटी एवं प्रशासनिक क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों को खुले रूप से साझा करें।

महानिदेशक ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के अधिकारियों को नवीनतम प्रौद्योगिकी जैसे साइबर सुरक्षा, एआई आदि में उद्योग प्रमाणन प्राप्त करने पर बल दिया।

कार्यक्रम की झलकियां

श्री सुनील शर्मा, उपमहानिदेशक ने श्री आशेष अग्रवाल, उपमहानिदेशक का स्वागत किया, जिन्होंने 01 मई 2025 को एस.आई.ओ. उ.प्र. के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

श्री आशेष कुमार अग्रवाल**,** उपमहानिदेशक एवं **एस.आई.ओ.** उ.प्र. ने 4 जून 2025 को 19 जिला केंद्रों में डी.आई.ओ./ए.डी.आई.ओ./डी.आई.ए. के साथ परस्पर संवादात्मक समीक्षा की।

3 जून 2025 को उ.प्र. के उपमहानिदेशक एवं **एस.आई.ओ.** उ.प्र. श्री आशेष कुमार अग्रवाल ने 19 जिला केंद्रों में डी.आई.ओ./ए.डी.आई.ओ./डी.आई.ए. के साथ समीक्षा की।

5 जून 2025 को उ.प्र. के उपमहानिदेशक एवं ए**स**.आई.ओ.. श्री आशेष कुमार अग्रवाल ने 18 जिला केंद्रों में डी.आई.ओ./ए.डी.आई.ओ./डी.आई.ए. के साथ समीक्षा की।

6 जून 2025 को श्री आशेष कुमार अग्रवाल, उपमहानिदेशक एवं ए**स**.आई.ओ. उ.प्र., ने 19 जिला केंद्रों में डी.आई.ओ./ए.डी.आई.ओ./डी.आई.ए. के साथ समीक्षा की।

उ.प्र. के उपमहानिदेशक एवं ए**स**.आई.ओ. श्री आशेष कुमार अग्रवाल ने उ.प्र. सरकार के नव नियुक्त मुख्य सचिव श्री एस. पी. गोयल, आईएएस से शिष्टाचार भेंट की।

रा.सू.वि.के., मुख्यालय, नई दिल्ली की टीम ने 22-23 जुलाई 2025 के दौरान रा.सू.वि.के. उ.प्र. का दौरा कर डिजिटल उत्पाद 'ई-तुला' (कानूनी मापविज्ञान प्रशासन का ई-रूपांतरण) का अध्ययन किया।

रा.सू.वि.के., मुख्यालय, नई दिल्ली के अनुबंध शासन समूह के प्रमुख एवं उपमहानिदेशक श्री संदीप सिंघल के साथ नीति-संबंधी चर्चाएँ की गईं।

रा.सू.वि.के., मुख्यालय के उपमहानिदेशक श्री आई. पी. एस. सेठी ने रा.सू.वि.के., उ.प्र. के विभागाध्यक्षों के साथ समीक्षा की एवं 3 सितंबर 2025 को रा.सू.वि.के. उ.प्र. डेटा केंद्र/ निकनेट-एन.के.एन. नेटवर्क संचालन केंद्र का भी दौरा किया।

कार्यक्रम की झलकियां

सम्भल संवाद ऐप, रा.सू.वि.कें. सम्भल द्वारा विकसित, का शुभारंभ 7 अगस्त 2025 को मा. मुख्यमंत्री **योगी आदित्यनाथ** द्वारा किया गया।

रा.सू.वि.कें. प्रयागराज जिला केंद्र में ई-ऑफिस के क्रियान्वयन से डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा मिला।

कांवड़ यात्रा की तैयारी के लिए आयोजित अंतर्राज्यीय बैठक में रा.सू.वि.कें., उ.प्र. ने तकनीकी सहयोग प्रदान किया।

लखनऊ हवाई अड्डे पर विदेशी यात्री पहचान-आधारित त्वरित यात्रा सुविधा के ई-गेट का वर्चुअल उद्घाटन माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने किया।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मोबाइल ऐप का विकास राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, उत्तर प्रदेश की पहल है।

परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश में बिक्री बिंदु मशीन आधारित भुगतान प्रणाली प्रारंभ की गई।

सेवायोजन पोर्टल उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार सशक्तिकरण का माध्यम बना।

3 सितंबर 2025 को उ प्र के मा. मुख्यमंत्री द्वारा 'विकसित उत्तर प्रदेश समर्थ उत्तर प्रदेश@2047' पोर्टल (samarthuttarpradesh.up.gov.in) का शुभारंभ किया गया।

माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से माध्यमिक विद्यालयों के नव नियुक्त सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए।

महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंस सत्र

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 महीनों में 1,500 से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित किए। इनमें से 46 वीडियो कॉन्फ्रेंस सत्र अत्यंत अति महत्वपूर्ण व्यक्ति (माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री एवं सांसदों) के लिए थे, 1127 वीडियो कॉन्फ्रेंस केंद्रीय सूचना आयोग के लिए आयोजित किए गए और शेष राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों के लिए जैसे मुख्य सचिव कार्यालय, गृह विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग आदि के लिए किये गए।

भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 30 जून 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ए आई आई एम एस गोरखपुर के प्रथम दीक्षांत समारोह की शोभा बढ़ाई।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त 2025 को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में पीएम-किसान की 20वीं किस्त जारी की।

माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और माननीय मुख्यमंत्री उ प्र श्री योगी आदित्यनाथ ने 15 जून 2025 को लखनऊ में उ प्र पुलिस के 60,244 नियुक्ति पत्र वितरित किए।

नई नियुक्तियाँ

- **आज़मगढ़: श्री मिथिलेश कुमार, एसओई/एसबी**
- **अमरोहा: श्री कृष्णांत कुमार पाठक, एसओई/एसबी**
- **बाराबंकी: श्री एकांश शर्मा, एसओई/एसबी**
- **बिजनौर: श्री दीपांकर यादव, एसओई/एसबी**
- **पीलीभीत: श्री मयंक मिश्रा, एसओई/एसबी**
- **उ.प्र.रा.के.: श्री संजय कुमार साहू, कनिष्ठ सचिवालय सहायक**

मई-जून' 2025

- **चंदौली: श्री हरेन्द्र कुमार यादव, एसटीए-ए**
- **बांदा: श्री पंकज कुमार, एसटीए-ए**
- **जालौन: श्री यदुवीर सिंह, एसटीए-ए**
- **कन्नौज: श्री राजेश कुमार यादव, एसटीए-ए**
- **उ.प्र.रा.के: श्री मनीष कुमार शुक्ल, कनिष्ठ सचिवालय सहायक**

जुलाई-अगस्त'2025

सेवानिवृत्ति

अप्रैल 2025 में **श्री एस.एफ.ए. नक़वी**, उपमहानिदेशक और **श्री शक्ति अग्रवाल**, वैज्ञानिक-ई के सेवानिवृत्ति समारोह का आयोजन किया गया।

31 जुलाई 2025 को **श्री हेमंत कुमार अरोरा**, वैज्ञानिक-एफ के सेवानिवृत्ति समारोह का आयोजन किया गया, जिन्होंने एक उत्कृष्ट करियर के बाद सेवा से निवृत्ति ली।

28 अगस्त 2025 को **श्री लाल चंद यादव**, सहायक जिला सूचना अधिकारी एवं वैज्ञानिक-एफ के सेवानिवृत्ति समारोह का आयोजन किया गया।

पुरस्कार और प्रशंसा

श्री आशेष अग्रवाल, उपमहानिदेशक एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी ने निक्सी की 30वीं वर्षगांठ पर राजस्व वृद्धि में उत्तर प्रदेश की उपलब्धि हेतु सम्मान प्राप्त किया।

श्री प्रभात मिश्रा, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सम्भल को आईटी और ई-गवर्नेंस में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रशंसा प्रमाणपत्र मिला।

Justice Vivek Chaudhary **High Court, Lucknow**

LETTER OF APPRECIATION

I extend my sincere appreciation to **Mr. Pradeep Kumar, Emp. (Code 6155) Joint Director (IT), NIC deputed at Allahabad High court, Lucknow**, for the outstanding work that has been done in developing the in-house customized software solutions using Open-Source Technologies for the Hon'ble Courts as a part of process reform.

....

I look forward to seeing the team take on more challenging and impactful projects in the future. Keep up the excellent work!

(Vivek Chaudhary)

Lucknow,
Dated: July 16, 2025

Mr. Pradeep Kumar,
Joint Director (IT), NIC deputed at High Court

श्री प्रदीप कुमार, संयुक्त निदेशक (आईटी), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ द्वारा प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया।

राजभाषा से संबंधित

Words	Hindi Synonyms	Usages in English	Usages in Hindi
sanction	अनुमति देना, स्वीकृति देना, मान्यता देना	The Government sanctioned funds for the new project.	सरकार ने नए परियोजना के लिए धनराशि की स्वीकृति दी।
implement	लागू करना, क्रियान्वित करना, कार्यान्वित करना	The department implemented strict rules for data security.	विभाग ने डाटा सुरक्षा के लिए कड़े नियम लागू किए।

प्रशिक्षण और प्रस्तुतियाँ

1 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, उत्तर प्रदेश राज्य केंद्र, लखनऊ में सार्वजनिक खरीद और अनुबंध प्रबंधन पर प्रस्तुति दी गई।

20 जून 2025 को आयोजित साइबर सुरक्षा अंतःक्रियात्मक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी एवं उपमहानिदेशक श्री आशेष कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में किया गया। ।

एक्कॉप्स द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, उत्तर प्रदेश के लिए आईटी समाधान की खोज पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें रिमोट एक्सेस और सुरक्षा पर चर्चा हुई।

नेशनल ई-विधान ऐप्लीकेशन (NeVA) द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश विधानसभा का ऐतिहासिक 24 घंटे का अनवरत सत्र

- उत्तर प्रदेश विधानसभा एवं विधान परिषद का वर्ष 2025 का दूसरा सत्र दिनांक 11 से 14 अगस्त, 2025 तक आयोजित किया गया। इस सत्र का समापन तिथिवार अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार 13–14 अगस्त को कुल 28 घंटे की निरंतर बैठक के साथ संपन्न हुआ| यह कार्यवाही भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय (MoPA) एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र , उत्तर प्रदेश के सहयोग से सफलतापूर्वक आयोजित की गई।
- नियम 103 के अंतर्गत "**विकसित भारत – विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत – आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश**" विषय पर प्रस्ताव प्रस्तुत कर उस पर विस्तार से चर्चा की गई। चर्चा के दौरान वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के दृष्टिकोण तथा नागरिकों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के योगदान पर विशेष बल दिया गया।
- संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, उत्तर प्रदेश के संयुक्त प्रयासों से नेवा एप्लिकेशन के सभी मॉड्यूल अब विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों में पूर्ण रूप से संचालित हो गए हैं। इस उपलब्धि के साथ उत्तर प्रदेश संपूर्ण रूप से नेवा को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।

16 अगस्त, 2025

उत्तर प्रदेश विधानसभा ने फिर रचा इतिहास

मानसून सत्र

■ अजित खरे

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने एक और रिकार्ड बना लिया है। यूपी पहली विधानसभा है जिसने संविधान, सतत विकास के लक्ष्य व विकसित भारत विकसित यूपी विजन डाक्यूमेंट पर लगातार लंबी व विशेष चर्चा की। इसके जरिए सामाजिक न्याय व विकास की नई दृष्टि विकसित करने की पहल राज्य में हुई है।

इसके जरिए देश भर का ध्यान यूपी विधानसभा पर गया है जो पिछले कुछ सालों से नवाचार, तकनीक व भव्यता पर खासा जोर दे रहा है। विकसित यूपी 2047 का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो खाका पेश किया है, उसे अब आने वाले वर्षों पर चरणवार काम होगा।

1950 में पहली बार रात एक बजे तक चला था सदन : विधानसभा के रिकार्ड बताते हैं कि 16 सितंबर 1950 को पहली बार विधान सभा आधी रात तक चली थी। सुबह 11 बजे से आधी रात 1:10 मिनट तक सदन चला। सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना 2 अक्तूबर 2019 को। योगी सरकार में पहली बार विधान सभा 36 घंटे तक चली थी। सतत विकास के लक्ष्यों पर चर्चा के वक्त कुल 304 विधायक मौजूद रहे थे। चर्चा सुबह 11 बजे शुरू होकर दूसरे दिन यानि तीन अक्तूबर को रात 11:42 पर खत्म हुई। इस तरह 36 घंटे लगातार सदन चलने का रिकार्ड बना। इसके बाद संविधान दिवस के मौके पर 26 नवंबर 2019 को विधानसभा मंडप में 12 बजे से विशेष सत्र का आयोजन हुआ। इसमें दोनों सदनों के सदस्य शामिल हुए। संविधान की महत्ता पर यह चर्चा लगातार चली और शाम 6:22 मिनट पर यह समाप्त हुई। इसके अलावा यूपी विधानसभा केवल महिलाओं के लिए अलग से विशेष चर्चा का आयोजन कर चुकी है।

कोई सोता दिखा तो कोई ऊंघता : लंबी चर्चा के दौरान मंत्री स्वतंत्र देव के सोते हुए फोटो वायरल हो गई। कई सदस्य थकान के चलते ऊंघते दिखे। गैर भाजपा दलों के कई विधायकों की चाहत थी कि उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने बोलने का मौका मिले। सदन में जब वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने शेर पढ़ा तो सपा के इकबाल महमूद भी पीछे नहीं रहे।

189 मंत्री व विधायकों ने की शिरकत : इस चर्चा में 189 विधायकों ने शिरकत की। इसमें 141 भाजपा व सहयोगी दलों के हैं। इसके अलावा 42 सपा के, तीन निर्दलीय, दो जनसत्ता दल के व एक कांग्रेस के विधायक ने भी अपने विचार रखे। मुख्यमंत्री, दोनों उपमुख्यमंत्री के अलावा कई मंत्रियों ने अपने विभाग के दृष्टि पत्र रखे। सरकार ने मंत्रियों की रोस्टर के हिसाब से ड्यूटी लगाई थी। खुद सतीश महाना व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रात में जागे और सदन में मौजूद रहे।

यूपी विधानसभा का सत्र 24 घंटे अनवरत चला जिसमें विजन डॉक्युमेंट पर मंत्री और विधायकों ने अपनी योजनाओं को पेश किया।

बाहर बारिश, अंदर सदन में चर्चा

आधी रात को जब बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी तब भी सदन में बड़ी तादाद में विधायक मौजूद होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। सदन चलने के कारण, सुरक्षाकर्मी, मार्शल, मंत्रियों का स्टाफ व विधानसभा के रक्षक भी अपनी ड्यूटी पर रहे।

महाना, अधिष्ठाता मंडल ने संभाला मोर्चा

सतीश महाना, अधिष्ठाता मंडल ने संभाला मोर्चा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी लंबे वक्त तक सदन चलाया और उनकी अनुपस्थिति में सिद्धार्थनाथ सिंह, मंजु शिवाच, अनुपमा जयसवाल, मनोज पांडेय, पंकज सिंह आदि ने सदन का संचालन किया। मंत्री भी तय समय से ज्यादा बोले।

संजय निषाद व सपा सदस्यों में नोकझोंक हुई

चर्चा में दो बार नोकझोंक देखने को मिली और एक बार विपक्ष वेल में उतरा, हालांकि सदन को स्थगित करने की नौबत नहीं आई। स्पीकर सतीश महाना ने विषय से अलग हट कर बोलने पर मंत्री संजय निषाद को टोका। उन्होंने कहा कि अब आप बैठ जाइये अन्यथा आपका माइक बंद करना पड़ेगा। मंत्री ने फूलन देवी की हत्या में सपा का हाथ बताया तो सपा सदस्य नारेबाजी कर वेल में आ गए।

देर रात से सुबह तक बोले 12 विभागों के मंत्री

अनिल कुमार, दयाशंकर सिंह, दयाशंकर मिश्र दयालु, बृजेश सिंह बोले। इसके बाद 3 से सुबह 6 बजे तक मंत्री अनिल राजभर, गिरीश चंद यादव, बलदेव सिंह औलख, दिनेश खटिक, संजीव गौड़, रामकेश निषाद, मनोहर लाल, केपी मलिक बोले। भोर में सूर्य प्रताप शाही, गुलाब देवी ने भाषण दिया।

दोनों पक्षों ने गिनाई अपनी उपलब्धियां

सपा ने विजन डाक्यूमेंट पेश कर भाजपा को घेरने की कोशिश की। सपा के अधिकांश सदस्यों ने अपने भाषणों में अखिलेश यादव के मुख्यमंत्रित्वकाल की उपलब्धियां को प्रमुखता से रखा। तो भाजपा सदस्यों ने योगी राज के कामकाज को सामने रखा। कुछ ही सदस्यों का भाषण सियासत से दूर रहा।

तीन दिन के सत्र में कुल 32:28 घंटे चला सदन

11 से 14 के बीच सदन कुल 32:28 घंटे चला। सपा के हंगामे के चलते 43 मिनट कार्रवाई स्थगित रही। 13 अगस्त से 14 अगस्त तक सदन 27:36 घंटे चला। बांके बिहारी मंदिर न्यास व मंत्रियों व विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने संबंधी विधेयक समेत 10 विधेयक पास किए गए।

उत्तर प्रदेश राज्य आबकारी विभाग द्वारा ई-लॉटरी प्रणाली के माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी दुकानदार व्यवस्थापन प्रक्रिया का सफल क्रियान्वयन

उत्तर प्रदेश राज्य आबकारी विभाग ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के तकनीकी सहयोग से देशी शराब, विदेशी शराब, बीयर तथा भांग की दुकानों के वितरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करते हुए एक अभिनव पहल की है। इस डिजिटल प्रक्रिया का उद्देश्य चयन प्रणाली को सरल, सुगम एवं प्रभावी बनाना रहा, जिसमें NIC की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही।

वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु कुल **27,423** दुकानों का आवंटन **पाँच चरणों** में **ई-लॉटरी प्रणाली** के माध्यम से किया गया। इस प्रक्रिया में देशी शराब की दुकानें, **मिश्रित दुकानें (विदेशी शराब एवं बीयर), मॉडल दुकानें तथा भांग की दुकानें** सम्मिलित थीं।

इस पहल को अभूतपूर्व जनसमर्थन प्राप्त हुआ। केवल 10 दिनों के भीतर **1.62 लाख** से अधिक आवेदकों ने पंजीकरण कर लॉटरी प्रक्रिया में भागीदारी की, जो डिजिटल प्रक्रियाओं के प्रति आमजन की स्वीकृति तथा जागरूकता को दर्शाता है।

आवेदकों की सुविधा हेतु एक समर्पित वेब पोर्टल विकसित किया गया, जिसके माध्यम से वे **मोबाइल नंबर तथा पैन** कार्ड के माध्यम से सरलता से पंजीकरण कर अपनी पसंद की दुकानों हेतु आवेदन कर सकते थे। राज्य सरकार की नीति के अनुसार यह सुनिश्चित किया गया कि **किसी भी आवेदक को राज्य भर में दो से अधिक दुकानें आवंटित न की जाएं**, जिससे प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिले और एकाधिकार की संभावना को रोका जा सके।

प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं निष्पक्षता को और अधिक सशक्त बनाने हेतु **आईआईटी कानपुर** द्वारा सत्यापित **ई-लॉटरी एल्गोरिथ्म** का प्रयोग किया गया। साथ ही, वास्तविक लॉटरी से पूर्व **सिमुलेशन सुविधा** उपलब्ध कराई गई, जिससे आवेदक प्रक्रिया को भली-भांति समझ सकें और निष्पक्षता के प्रति उनका विश्वास और भी प्रगाढ़ हो। पूरी ई-लॉटरी प्रक्रिया राज्य सरकार के **वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों** की देखरेख में सम्पन्न हुई। इसके अतिरिक्त **संबंधित जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (DIO/ADIO) तथा जिला आबकारी अधिकारी** निर्धारित स्थलों पर उपस्थित रहकर इस प्रक्रिया की निगरानी सुनिश्चित करते रहे।

यह पहल न केवल डिजिटल सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय कदम है, अपितु लोक भागीदारी, पारदर्शिता और विश्वास आधारित प्रणाली की स्थापना की दिशा में भी एक प्रेरणास्पद उदाहरण प्रस्तुत करती है।

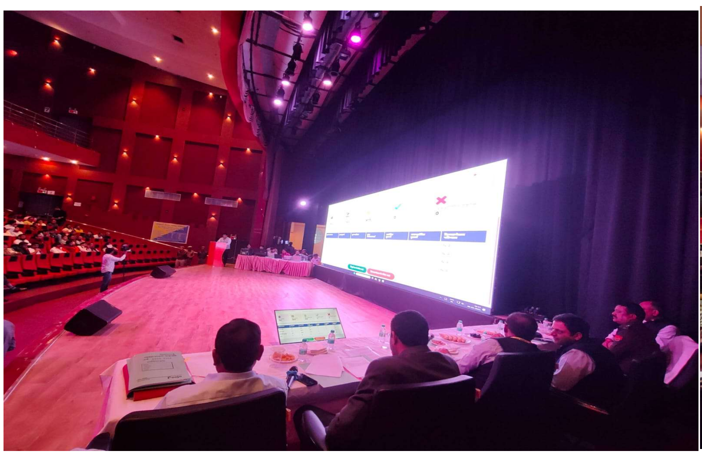

जिलों की संक्षिप्त जानकारी

जिला ललितपुर - ई-गवर्नेंस और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक

बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित जनपद ललितपुर, जोकि 1974 में स्थापित हुआ, सांस्कृतिक प्राचीनता और आधुनिक डिजिटल शासन का अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत करता है। प्रशासनिक रूप से ललितपुर 5 तहसीलों और 6 विकास खंडों में विभाजित है।

जनपद ललितपुर में एन०आई०सी० टीम मिशन-क्रिटिकल डिजिटल सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करती है। इनका कार्य नेटवर्क का निर्बाध संचालन (निकनेट, यूपीस्वान), डिजिटल सेवा प्रदान करना (वीडियो कॉन्फ्रेंस प्लेटफ़ॉर्म, S3waas वेबसाइट) और सशक्त व् सुरक्षित आईटी प्लेटफार्म जनपद प्रशासन को उपलब्ध कराना शामिल है।

जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदारी की निगरानी, आधारभूत संरचना का रख-रखाव, चुनाव के समय आईटी गतिविधियों संचालन और सरकारी कर्मचारियों के लिए ई-गवर्नेंस क्षमता विकास कार्यशालाएँ भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं।

"एनआईसी ललितपुर ने कई प्रमुख प्रौद्योगिकी-आधारित परियोजनाओं की परिकल्पना और क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाई है, जिसके द्वारा शासन व्यवस्था और जनसेवा वितरण में सीधे सुधार हुआ है।"

- श्री अक्षय त्रिपाठी, आईएएस
पूर्व जिलाधिकारी, ललितपुर (उ.प्र.)

क्लीन फ्यूचर:

स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ

यह ललितपुर शहर की पुरस्कार विजेता स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट प्रणाली है तथा वेब और मोबाइल इंटरफेस के माध्यम से समय पर कचरा संग्रह सुनिश्चित करती है।

इस प्रणाली ने घर-घर कचरा संग्रहण प्रक्रिया का डिजिटलकरण किया, जिससे उच्च अधिकारियों और प्रशासकों को दैनिक कचरा संग्रह की पूरी जानकारी मिली।

इस नवाचार को भारत सरकार के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस अवार्ड्स 2025 में "ज्यूरी अवार्ड" से सम्मानित किया गया है ।

NAVIGATE: यह एक जीपीएस-सक्षम मोबाइल और वेब प्लेटफ़ॉर्म है जोकि चुनाव कार्मिकों के नियोजन व् पर्यवेक्षण में क्रांति ला रहा है। यह सेक्टर मजिस्ट्रेटों की रियल-टाइम ट्रैकिंग करने में सक्षम है तथा चुनाव आयोग को भेजे जानी वाली रिपोर्ट्स का स्वत: संकलन कर नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

ललितपुर जिले ने NAVIGATE को लागू कर चुनावी प्रबंधन में तकनीकी क्रांति की शुरुआत की है । यह प्लेटफ़ॉर्म रियल-टाइम ट्रैकिंग, निर्बाध संचार और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। यह ईवीएम परिवहन की सुरक्षा में सहयोग करता है व् चुनावी प्रक्रिया के संचालन को सुव्यवस्थित करते हुए सम्बंधित अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ाता है।

जनपद ललितपुर ने **ई-ऑफिस के क्रियान्वन** में अग्रणी भूमिका निभाई है एवं उत्तर प्रदेश का पहला जिला बना जिसने जनपद प्रशासन के तीनो प्रमुख अंग राजस्व, पुलिस और विकास को ई-ऑफिस पर रोल-आउट किया है। डिजिटल नवाचार, त्वरित परियोजना रोल-आउट और डिजिटल समावेशन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाते हुए ललितपुर **आईसीटी-आधारित शासन व्यवस्था** को अपनाने वाला एक महत्वपूर्ण जनपद है। आने वाले समय में नगर में ए०आई० का उपयोग कर जन-केन्द्रित सेवाओं का सुधार व् विस्तार, विभागों में साइबर सुरक्षा को मजबूत करना, ई-गवर्नेंस में अंतिम मील तक डिजिटल साक्षरता बढ़ाना एन०आई०सी० जनपद एकक ललितपुर के प्रमुख लक्ष्य है।

- अर्पित जैन सिंघई, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी० ललितपुर

प्रमुख परियोजनाएँ

नेक्स्ट-जेन दर्पण
उत्तर प्रदेश के प्रोजेक्ट्स के विश्लेषणात्मक समीक्षा के लिए डैशबोर्ड

नेक्स्ट-जेन दर्पण राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र का कॉन्फ़िगरेबल और द्विभाषी कॉपीराइट उत्पाद है, जो प्रशासन को विभागीय गतिविधियों औरयोजनाओं की त्वरित जानकारी डैशबोर्ड द्वारा प्रदान करता है।

माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शास्त्री भवन, लखनऊ में नेक्स्ट-जेन दर्पण और मुख्यमंत्री कमांड सेंटर का उद्घाटन किया।

उत्तर प्रदेश में कुल **950+ योजनाएँ (7150+ KPI)** पंजीकृत हैं, जिनमें से **180+ योजनाएँ** प्रमुख (Flagship) योजनाओं के रूप में चिह्नित की गई हैं। प्रमुख योजनाओं के तीन मुख्य वर्गों – **विकास, राजस्व और कानून एवं व्यवस्था** में जिलों/प्रभागों का मासिक रैंक तैयार किया जाता है, जिससे जिलों और विभागों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है।

खाद्यान्न खरीद व सार्वजनिक वितरण प्रणाली - खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश

यह प्रणाली पूर्ण स्वचालन सुनिश्चित कराते हुए मैनुअल कार्य व्यवस्था को बेहतर ढंग से एक सुरक्षित, इंटरऑपरेबल एवं स्केलेबल कंप्यूटराइज्ड प्लेटफ़ॉर्म के रूप में विकसित की गयी है। विभाग द्वारा लागू की गई प्रमुख डिजिटल प्रणालियाँ निम्नवत हैं:

ई-खरीद प्रणाली: यह प्रणाली गेहूँ, धान, मक्का, बाजरा एवं अन्य अनाज की खरीद का प्रबंधन करती है। इसमें किसान पंजीकरण, फसल खरीद, परिवहन, भुगतान (Public Financial Management System के माध्यम से), मिलर प्रबंधन एवं फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (FRK) प्रबंधन हेतु उन्नत मॉड्यूल सम्मिलित हैं।

राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली: यह प्रणाली राशन वितरण हेतु प्रदेश के लगभग 3.57 करोड़ परिवारों (15 करोड़ से अधिक सदस्य) के डेटा का प्रबंधन करती है। यह परिवार आईडी, ई-श्रम एवं आयुष्मान भारत (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना) हेतु आधारभूत डेटाबेस के रूप में भी कार्य करती है तथा लाभार्थियों के रिकॉर्ड को पारदर्शी, सत्यापित एवं अद्यतन बनाए रखने में सहायक है।

आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली: यह प्रणाली सार्वजनिक वितरण को सुचारू रूप से निष्पादित किये जाने के लिए डिजिटल रीढ़ के रूप में कार्य करती है। गोदामों से राशन दुकानों (Fair Price Shops) तक खाद्यान्न की आपूर्ति का प्रबंधन करती है। इसमें जीपीएस ट्रैकिंग, रियल टाइम रिपोर्टिंग एवं बायोमेट्रिक प्रमाणीकृत प्राप्ति आदि की सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

इलेक्ट्रॉनिक बिक्री बिंदु प्रणाली: यह प्रणाली लगभग 80,000 राशन वितरण केंद्रों पर ऑनलाइन खाद्यान्न वितरण का प्रबंधन करती है। यह ओटीपी युक्त द्वि-कारक प्रमाणीकरण, इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन (Electronic Weighing Scale) के साथ संयोजन, ऑफलाइन वितरण पुष्टि और एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (One Nation One Ration Card) के तहत अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करती है।

ई-परीक्षा
"बुद्धिमान, जानकार, कुशल और उच्च क्षमतावान उम्मीदवारों के लिए कागज रहित (पेपर लेस) भर्ती"

ई-परीक्षा, कागज़ रहित भर्ती के लिए एक पूर्ण डिजिटल समाधान है। यह अभ्यर्थियों को पंजीकरण से लेकर अंतिम चयन तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से करने में सक्षम बनाता है और साथ ही भर्ती एजेंसियों को पारदर्शी और कुशल परीक्षा आयोजित करने में भी सहायता करता है।

- अधियाचन सेवा (eAdhiyachan)
- एकल पंजीकरण सेवा (OTR)
- दस्तावेज़ संग्रहण और सत्यापन सेवा (eLocker)
- भुगतान गेटवे सेवा (ePGS)
- संचार प्रबंधन सेवा (ePCMS)
- शिकायत निवारण प्रबंधन सेवा (ePGRS)
- दस्तावेज़ प्राप्ति और प्रेषण प्रबंधन सेवा (ePRDS)
- कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा (ePCBOT)
- परीक्षा प्रबंधन सेवा (ePEMS)

डिजिटल उपकरणों एवं प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सुशासन सशक्तिकरण

एनआईसी उत्तर प्रदेश ने 04 सितम्बर 2025 को लखनऊ स्थित होटल 'हिल्टन गार्डन इन' में **"डिजिटल उपकरणों एवं प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सुशासन सशक्तिकरण"** विषयक **कार्यशाला** का आयोजन किया।

कार्यशाला का उद्घाटन पारंपरिक दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ और वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के उद्घाटन भाषणों के साथ प्रारंभ हुआ, जिनमें श्री अनिल कुमार, आईएएस, अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री आलोक कुमार, आईएएस, प्रधान सचिव, योजना, उ प्र सरकार शामिल थे।

दोनों आईएएस अधिकारियों ने राज्य में ई-गवर्नेंस पहलों को सक्षम बनाने और उन्हें बनाए रखने में एनआईसी उ प्र की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की और एनआईसी को आईसीटी कार्यान्वयन की रीढ़ बताते हुए नागरिकसेवा वितरण और डिजिटल शासन में इसके योगदान को सम्मानित किया।

श्री इंदर पाल सिंह सेठी, उप महानिदेशक, एनआईसी नई दिल्ली ने अपने संबोधन में डिजिटल शासन के लिए एनआईसी की राष्ट्रीय दृष्टि पर जोर दिया और पारदर्शी और कुशल प्रशासन के लिए सुरक्षित, स्केलेबल और नागरिक केंद्रित आईसीटी प्लेटफॉर्म के महत्व को रेखांकित किया।

प्रतिभागियों ने वरिष्ठ एनआईसी विशेषज्ञों (नई दिल्ली और तेलंगाना) द्वारा आयोजित तकनीकी सत्रों में भाग लिया, जिनमें सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म, लेन-देन विश्लेषण, सहयोगी उपकरण और क्लाउड-आधारित समाधानों पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई, जिन्हें शासन प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- **Gov.in Secure Intranet (govintranet.gov.in/)** डॉ. ओम प्रद्युम्न गुप्ता, निदेशक (आईटी), एनआईसी दिल्ली ने Gov.in को एक सुरक्षित, मजबूत और एकीकृत इंट्रानेट प्लेटफ़ॉर्म के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे विशेष रूप से सरकार से कर्मचारी (G2E) सेवाओं के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **eTaal (Electronic Transaction Aggregation and Analysis Layer) (https://etaal.gov.in/)** डॉ. रितेश के. द्विवेदी, संयुक्त निदेशक (आईटी), एनआईसी दिल्ली ने दिखाया कि कैसे eTaal ई-गवर्नेंस सेवाओं में इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन डेटा को समेकित और विश्लेषित करता है और वास्तविक समय में आंकड़े प्रदान करता है। वर्तमान में उप्र eTaal पोर्टल पर शीर्ष पांच प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल है।
- **CollabFiles (collabfiles.gov.in/)** सुश्री वाई. श्रीवाणी, निदेशक (आईटी), एनआईसी तेलंगाना ने CollabFiles को प्रदर्शित किया, जो एनआईसी द्वारा विकसित एक स्वदेशी, वेब-आधारित और क्लाउड-सक्षम ऑफिस सूट है। यह सरकारी उपयोगकर्ताओं को दस्तावेज़, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन को सुरक्षित रूप से बनाने, साझा करने और वास्तविक समय में सहयोग करने की सुविधा देता है।

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र
उत्तर प्रदेश राज्य केंद्र
तृतीय तल, योजना भवन
9, सरोजिनी नायडू मार्ग
लखनऊ (उत्तर प्रदेश) - 226001

भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
एनआईसी National Informatics Centre

ईमेल: sio-up@nic.in
फोन: 0522-2238415
वेबसाइट: https://up.nic.in